

संपादकीय

विवाद बढ़ाने का काम करता चीन

शवसगाम घाटी को लेकर भारत को पूरी तरह चौकस रहने की आवश्यकता...

आज भारत के एकमात्र भरोसेमंद दोस्त रूस ने खुद को यूएन के साथ अपने अंतहीन युद्ध में उलझा लिया है और इस कारण काफी कमजोर हो चुका है। चीन-विरोध के नाम पर भारत की मदद का फैसला कर सकने वाला अमेरिका भी इस समय दुनिया भर के साथ आर्थिक टकराव में बुरी तरह उलझा हुआ है...

जब अमेरिका भारत के समक्ष समस्याएं खड़ी करने से बाज नहीं आ रहा है, तब चीन भी चिंता का कारण बन रहा है। वास्तव में चीन ने जबसे 1951 में तिब्बत पर जबरन कब्जा करके भारत-तिब्बत सीमा को भारत-चीन सीमा में बदल दिया, तबसे उसके भारत-विरोधी रुख में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। पहले तो उसने 1962 में तिब्बत को छत्रवनी की तरह इस्तेमाल करके भारत पर हमला किया। इसके बाद से वह सैकड़ों किलोमीटर लंबी इस सीमा पर उकसावे की कोई न कोई हकत कर रहा है।

आर्थिक और सैनिक शक्ति हासिल करने के बाद तो चीन की यह आक्रामकता सीधी दादागिरी में बदल चुकी है। पहले वह भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के इलाकों पर जुबानी दावे करता था, लेकिन 2017 में डोकलाम घाटी पर कब्जे की कोशिश में मुंह की खाने के बाद उसने पूरी सीमा पर बड़े पैमाने पर सैन्य निर्माण शुरू करके भारत के लिए नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। पिछले दिनों अंतरिक्ष से सीमाओं की टोह लेने वाले भारतीय उपग्रहों से पता चला कि लद्दाख में चीनी कब्जे वाले शकसगाम इलाके में चीनी सेना एक ऐसी सड़क बना रही है, जो भारत-पाकिस्तान और चीन के इस मिलन क्षेत्र में सियाचिन की सुरक्षा के लिए नए खतरे पैदा कर सकती है।

शकसगाम घाटी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के भारत में विलय के बाद भारत का हिस्सा थी, लेकिन अक्टूबर 1947 में उस पर हमले में पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था। 1962 के भारत-चीन युद्ध के एक साल बाद ही पाकिस्तान ने चीन को खुश करने के लिए 1963 की एक संधि के तहत शकसगाम का लगभग 5,180 वर्ग किमी क्षेत्र चीन को सौंप दिया। रणनीतिक दृष्टि से शकसगाम के भौगोलिक महत्व को इससे समझा जा सकता है कि यह पाकिस्तान द्वारा भारत से छीने गए गिलगित-बाल्टिस्तान और चीन द्वारा 1949 में कब्जाए गए ईस्ट-तुर्किस्तान (चीन द्वारा दिया गया नया नाम 'शिनजियांग') को आपस में जोड़ता है।

इसके अलावा यह सियाचिन के बहुत निकट है जो शकसगाम और भारत के उस अक्सई चिन को अलग करता है, जिस पर 1950 के दशक में चीन ने गुप्तचुप कब्जा कर लिया था। शकसगाम में चीन की यह नई से क बन जाने के बाद दुनिया के सबसे ठंडे युद्धक्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तानी हमलों से बचाने में जुटी भारतीय सेनाओं के लिए खतरा दोबारा हो जाएगा। आज सियाचिन पर उपस्थिति के कारण भारतीय सेना चीन के सैनिक महत्व वाले कराकोरम हाईवे पर नजर रख सकती है, जिसकी वजह से सियाचिन चीन के आंख की किरकिरी बना हुआ है। इसी क्षेत्र पर कब्जे के लिए 2021 में चीनी सेना ने गलवन में धोखे से हमला किया था।

दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में गिने जाने वाले इस क्षेत्र में से कों के सैनिक महत्व को इससे समझा जा सकता है कि गलवन कांड के तुरंत बाद भारतीय सेना ने जिस गति और संख्या के साथ चीनी सैनिकों पर जवाबी हमला करके चीन को झकझोर दिया, वह केवल इसलिए संभव हो पाया कि उससे पहले ही भारतीय सेनाओं को लेह और श्योंक से गलवन होते हुए दौलतबगे ओल्डी तक पकड़ी से क मिल चुकी थी। मोदी सरकार को इसका श्रेय जाता है कि उसने भारत-तिब्बत सीमा पर लगाने वाली लगभग हर चौकी को 70 से ज्यादा नई और बारहमासी से कों से जो दिया है।

शिष्टाचार बनाम दिखावा: क्या सत्ता की निकटता मर्यादा से ऊपर हो गई है?

शासकीय कार्यालयों से लेकर राजनीतिक मंचों तक बदलता व्यवहार चिंता का विषय...



रवि सिंह कोरिया, छत्तीसगढ़

शिष्टाचार केवल आचरण का विषय है इसे न तो थोपा जा सकता है और न ही यह किसी नियम या अधिनियम से अनिवार्य होता है, फिर भी भारतीय सामाजिक परंपरा में इसका विशेष महत्व रहा है, चाहे पारिवारिक जीवन हो, गुरु-शिष्य परंपरा हो या फिर शासकीय कार्यालयों की कार्यसंस्कृति मर्यादा, सम्मान और संयम को हमेशा समाज की पहचान माना गया है, पुराने समय में गुरु-शिष्य परंपरा केवल चरण वंदन या औपचारिक आदर तक सीमित नहीं थी, शिष्य अपने गुरु के प्रति सम्मान भाव इतना गहरा रखते थे कि यदि गुरु पैदल चल रहे हों और शिष्य किसी वाहन में, तब भी शिष्य आगे निकलना अनुचित मानते थे। उस दौर में यही संस्कार समाज को एक आदर्श स्वरूप प्रदान करते थे।

आज हर कोई खुद को सबसे बड़ा साबित करने में लगा

चाहे अधिकारी हों, कर्मचारी हों, नेता हों, युवा नेता हों या आम नागरिक—हर कोई अपनी अहमियत दिखाने को प्राथमिकता देने लगा है, विशेष रूप से युवा वर्ग में यह प्रवृत्ति तेजी से उभरती नजर आ रही है, पहचान बनाने की जल्दबाजी, शीर्ष पर पहुंचने की



शासकीय कार्यालयों में भी दिखावा था संस्कारों का प्रभाव

एक समय था जब शासकीय कार्यालयों में भी पद के अनुरूप सम्मान और व्यवहार स्वतः दिखाई देता था। अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक—सभी मर्यादा के दायरे में रहते थे, प्रोटोकॉल केवल नियमों तक सीमित नहीं था, बल्कि आचरण और व्यवहार से स्वतः प्रकट होता था, लेकिन समय के साथ स्थितियां तेजी से बदली हैं, आज हालात यह हैं कि शिष्टाचार धीरे-धीरे पीछे छूटता जा रहा है और स्वयं को महत्वपूर्ण साबित करने की होड़ आगे बढ़ती जा रही है।

उतावली और स्वयं को विशेष सिद्ध करने की बेचैनी कई बार व्यवहारिक मर्यादा को पीछे छोड़ देती है। यही कारण है कि शिष्टाचार का अभाव अब केवल राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि शासकीय कार्यालयों तक में दिखाई देने लगा है।

ताजा मामला कोरिया जिले से जुड़ा
कोरिया जिले से सामने आया एक मामला इन बदलते सामाजिक और राजनीतिक व्यवहारों पर गंभीर सवाल खड़े करता है, मामला एक ऐसे युवा से जुड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी अधिकृत या जिम्मेदार पद पर

नहीं है, बावजूद इसके वह स्वयं को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली दर्शाने का निरंतर प्रयास करता नजर आ रहा है, यह युवा न केवल बड़े नेताओं के आगमन पर संगठन से अलग जाकर स्वागत-सत्कार कार्यक्रम आयोजित करता दिखाई देता है, बल्कि हाल ही में उसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आई है जिसमें वह जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए नजर आता है।

कलेक्टर कार्यालय की वीडियो बनी चर्चा का विषय

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में

यह युवा जिला कलेक्टर के समक्ष जिस अंदाज में बैठा नजर आता है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, भले ही कलेक्टर कार्यालय में रखी कुर्सियां किसी बाध्य प्रोटोकॉल नियम से नहीं जुड़ी हों, लेकिन शिष्टाचार की दृष्टि से आम नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष मर्यादित ढंग से व्यवहार करें, वीडियो में बैठने की मुद्रा और हावभाव को लेकर यह चर्चा तेज है कि क्या यह व्यवहार प्रशासनिक गरिमा के अनुरूप था।

अनुशासन की पहचान रखने वाली पार्टी से जुड़ा मामला

चूंकि यह मामला सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव प्रदर्शित कर रहे एक युवा से संबंधित है, इसलिए प्रश्न और गहरे हो जाते हैं, भाजपा संगठन अपने अनुशासन और संगठनात्मक मर्यादा के लिए जानी जाती है, यही कारण है कि यह सवाल उठना स्वाभाविक है क्या संगठन से जुड़े होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति अनुशासन से ऊपर हो सकता है?

संगठन से अलग चलने की प्रवृत्ति

पार्टी के भीतर भी यह चर्चा आम है कि संबंधित युवा संगठन के कार्यक्रमों में नियमित सहभागिता नहीं करता, जिला संगठन से अलग हटकर गतिविधियां संचालित करता है, बड़े नेताओं के आगमन पर ही सक्रिय दिखाई देता है, स्वयं की अलग गिनती और पहचान स्थापित करने का प्रयास करता है, बताया जा रहा है कि वह अक्सर संगठनात्मक निर्णयों से इतर जाकर स्वागत-सत्कार कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे पार्टी के भीतर एकला चलो की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है।

कार्यकर्ताओं से दूरी, नेतृत्व से निकटता का प्रयास

जानकारी के अनुसार यह युवा जिले के पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से दूरी बनाए रखता है केवल शीर्ष नेताओं की उपस्थिति वाले कार्यक्रमों में सक्रिय रहता है, लगातार यह प्रयास करता है कि बड़े नेता उसे अलग तबज्जो दें यह व्यवहार संगठनात्मक संतुलन के विपरीत माना जा रहा है।

सवाल सिर्फ व्यक्ति का नहीं, प्रवृत्ति का है- यह मामला किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि उस प्रवृत्ति का प्रतीक बनता जा रहा है जिसमें सत्ता की निकटता को अधिकार समझ लिया जाता है, शिष्टाचार को कमजोरी माना जाने लगा है, अनुशासन से पहले प्रदर्शन को महत्व दिया जाता है, यह प्रवृत्ति यदि समय रहते नहीं रोकी गई, तो न केवल राजनीतिक संस्कृति बल्कि प्रशासनिक मर्यादा भी प्रभावित हो सकती है।

शिष्टाचार नियम नहीं, संस्कार है...

शिष्टाचार कोई लिखित कानून नहीं, बल्कि सामाजिक संस्कार है, यह पद से नहीं, सोच से जुड़ा होता है, और यही संस्कार किसी व्यक्ति की असली पहचान बनाते हैं, आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा नेतृत्व को धैर्य और मर्यादा का पाठ पढ़ना जाए, संगठनात्मक अनुशासन को केवल भाषणों तक सीमित न रखा जाए, और सत्ता की निकटता को व्यवहारिक सीमा का उल्लंघन न बनने दिया जाए, क्योंकि सत्ता अस्थायी होती है, लेकिन आचरण ही व्यक्ति की स्थायी पहचान बनाता है।

हनी ट्रैप: भय, बदनामी और अपराध का संगठित जाल



डॉ. सत्यवान सौरभ बड़वा, भिवानी, हरियाणा

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में हनी ट्रैप के जरिए आम नागरिकों को फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश न केवल एक अपराधिक नेटवर्क का खुलासा है, बल्कि समाज के भीतर गहराते भय, चुपपी और बदनामी की मानसिकता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। यह मामला दर्शाता है कि किस तरह मानवीय कमजोरियों, सामाजिक संकोच और कानूनी डर का इस्तेमाल कर कुछ गिरोह सुनियोजित तरीके से लोगों को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बर्बाद कर रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस गिरोह में शामिल कुछ महिलाएं योजनाबद्ध ढंग से आम नागरिकों से संपर्क साधती थीं, उनसे दोस्ती और भावनात्मक

नजदीकी बढ़ाती थीं, फिर उन्हें आपत्तिजनक परिस्थितियों में फंसा कर झूठे दुकर्म, अपहरण, मारपीट या अन्य गंभीर आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी देकर मोटी रकम वसूलती थीं। यह कोई आकस्मिक अपराध नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति के तहत संचालित संगठित अपराध था।

जांच एजेंसियों के अनुसार इस गिरोह की कार्यप्रणाली बेहद सुनियोजित और चरणबद्ध थी। पहले चरण में आरोपी महिलाएं सोशल मीडिया, फोन कॉल या व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से संभावित शिकार से दोस्ती करती थीं। धीरे-धीरे भावनात्मक या व्यक्तिगत नजदीकी बढ़ाई जाती थी, जिससे पीड़ित को किसी खतरे का आभास न हो। दूसरे चरण में पीड़ित को ऐसी स्थिति में ले जाया जाता था, जहां उसके खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री या परिस्थितियां बनाई जा सकें। इसके बाद तीसरे और सबसे खतरनाक चरण में शुरू होता था भय का खेल—झूठे मुकदमों, पुलिस कार्रवाई, सामाजिक बदनामी और परिवार की प्रतिष्ठा पर आंच की धमकियों के जरिए ब्लैकमेलिंग। कई मामलों में यह भी सामने

आया है कि आरोपी महिलाएं अकेली नहीं थीं। उनके पति, प्रेमी या अन्य पुरुष सहयोगी इस पूरे षड्यंत्र में सक्रिय भूमिका निभाते थे—कभी धमकी देने वाले बनकर, कभी फर्जी गवाह के रूप में और कभी कथित अपहरण या मारपीट की कहानी रचने में सहायक बनकर।



पुलिस के अनुसार इन मामलों में ब्लैकमेलिंग, अवैध रूप से बंधक बनाना, अपहरण, मारपीट, लूट और आपराधिक षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। यह स्पष्ट करता है कि यह अपराध केवल नैतिक या सामाजिक दायरे तक सीमित नहीं, बल्कि विधि व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती है। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ आरोपी महिलाएं पहले भी हनी ट्रैप के मामलों में जेल जा चुकी हैं, जबकि कुछ के खिलाफ अन्य आपराधिक प्रकरण अभी अनुसंधान के अधीन हैं। इसका

अर्थ यह है कि यह अपराध किसी एक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि लंबे समय से सक्रिय एक नेटवर्क का हिस्सा है, जो बार-बार नए शिकार तलाशता रहा।

इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि अधिकांश पीड़ित सामाजिक बदनामी के भय से लंबे समय तक सामने नहीं आए। भारतीय समाज में आज भी व्यक्तिगत संबंधों, नैतिकता और इज्जत को लेकर गहरी संवेदनशीलता है। इसी मानसिकता का लाभ उठाकर ऐसे गिरोह लोगों को चुप रहने पर मजबूर कर देते हैं।

पीड़ित यह सोचकर डरते हैं कि यदि उन्होंने पुलिस से संपर्क किया तो समाज, परिवार या कार्यस्थल पर उनकी छवि खराब हो जाएगी। इसी डर का इस्तेमाल कर आरोपी बार-बार रकम वसूलते रहे। कई मामलों में पीड़ितों से लाखों रुपये तक की उगाही की गई, फिर भी धमकियों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि ऐसे मामलों में चुपपी अपराधियों को और मजबूत करती है। जितना अधिक समय पीड़ित डर के कारणा चुप रहता है, उतना ही अधिक वह अपराधी के नियंत्रण में चला जाता है। यही कारण है कि भीलवाड़ा जिला पुलिस अशोधक

धमेंद सिंह ने आमजन से अपील की है कि ऐसे किसी भी मामले में भयभीत न हों और तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया है कि पीड़ित की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और जांच के दौरान उसकी सुरक्षा और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। महिला हो या पुरुष—किसी भी आरोपी को कानून के दायरे से बाहर नहीं रखा जाएगा।

यह मामला एक और संवेदनशील प्रश्न उठाता है—कानून का दुरुपयोग। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून समाज के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, लेकिन जब इन्हें कानूनों का इस्तेमाल झूठे आरोपों और ब्लैकमेलिंग के लिए किया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान वास्तविक पीड़ितों को होता है।

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि हनी ट्रैप जैसे मामलों को उजागर करना महिलाओं के खिलाफ नहीं, बल्कि कानून के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई है। न्याय प्रणाली की साख तभी बनी रह सकती है जब वह हर मामले को निष्पक्षता से देखे—चाहे आरोपी महिला हो या पुरुष। हनी ट्रैप जैसे संगठित अपराध केवल पुलिस कार्रवाई से पूरी तरह खत्म नहीं हो सकते। इसके लिए समाज को भी अपनी

सोच में बदलाव लाना होगा। पीड़ित को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति, चरित्र पर सवाल उठाने की मानसिकता और बदनामी का भय—ये सभी अपराधियों के सबसे बड़े हथियार हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे मामलों में तेज, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई करे, वहीं समाज की जिम्मेदारी है कि वह पीड़ित के साथ खड़ा हो, न कि उसे कटघरे में खड़ा करे। भीलवाड़ा जिले में सामने आया हनी ट्रैप गिरोह का खुलासा एक चेतावनी है—आम नागरिकों के लिए भी और व्यवस्था के लिए भी। यह मामला दिखाता है कि अपराध अब केवल हथियारों से नहीं, बल्कि मानसिक दबाव, भय और सामाजिक कमजोरियों से भी किया जा रहा है। ऐसे समय में सबसे जरूरी है—जागरूकता, सहस्र और कानून पर भरोसा। जब पीड़ित चुपपी तोड़ेगी, तभी अपराधियों का यह जाल कमजोर पड़ेगा। पुलिस की अपील और कार्रवाई तभी सफल होगी, जब समाज डर के बजाय सच का साथ देगा। हनी ट्रैप केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि सामाजिक और कानूनी चुनौती है। इसका समाधान भी सामूहिक सहस्र, संवेदनशील सोच और निष्पक्ष न्याय में ही निहित है।

राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं लुभाने के लिए सरकारी खजाने से मुफ्त धन व अन्य वस्तुएं बांटने की घोषणा सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत



सुभाष बुडुवान वाला, रतलाम, मध्यप्रदेश

सभी राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं लुभाने के लिए सरकारी खजाने से मुफ्त धन व अन्य वस्तुएं बांटने की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार करने का स्वागत है।

सुप्रीम कोर्ट ने देश पर बढ़ते कर्ज और चुनावी लोकलुभावन घोषणाओं के बीच के खतरनाक संबंध को गंभीरता से लेते हुए सख्त याचिका की सुनवाई के लिए तत्परता दिखाई है, क्योंकि यह मुद्दा केवल चुनावी नैतिकता तक सीमित नहीं, बल्कि देश की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता से जुड़ा है। पिछले एक दशक में राज्यों का सार्वजनिक ऋण तेजी से बढ़ा है और रिजर्व बैंक की विभिन्न रिपोर्टें यह संकेत देती हैं कि कई राज्य अपने राजस्व का बड़ा हिस्सा केवल ब्याज चुकाने में खर्च कर रहे हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे और सुरक्षा जैसे जरूरी क्षेत्रों के लिए संसाधन सीमित हो रहे हैं।

चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त बिजली, पानी, यात्रा, राशन, नुकद हस्तान्तरण और अन्य रियायतों की घोषणाएं अब अपवाद नहीं, बल्कि प्रतियुद्ध का हथियार बन चुकी हैं, और यह प्रवृत्ति दक्षिण भारत तक सीमित न रहकर उत्तर और पश्चिम भारत में भी गहराई से फैल चुकी है। विडंबना यह है कि जो दल कभी इन योजनाओं को मुफ्त की रेवड़ी— कहकर कोसते थे, वही सत्ता या चुनावी दबाव में आकर उसी रास्ते पर चलते दिख रहे हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि बिना स्थायी राजस्व स्रोत के ऐसी योजनाएं राजकोपीय अनुशासन

को कमजोर करती हैं और भविष्य की पीढ़ियों पर कर्ज का बोझ डालती हैं। यह भी देखा गया है कि कई राज्यों में लोकलुभावन योजनाओं के कारण पूंजीगत व्यय घटा है, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए यह व्यय रोजगार सृजन और उत्पादकता बढ़ाने में सबसे अहम होता है। जनकल्याण के नाम पर दी जाने वाली ये रियायतें अल्पकाल में राहत तो देती हैं, लेकिन दीर्घकाल में लाभाधिकों को सरकारी सहायता पर निर्भर बनाकर उनकी कार्यक्षमता और आत्मनिर्भरता को प्रभावित करती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कई देशों ने चुनावी घोषणाओं के लिए वित्तीय उत्तरदायित्व कानून बनाए हैं, जिनके तहत यह स्पष्ट करना अनिवार्य होता है कि किसी वादे का वित्तीय स्रोत क्या होगा और उसका बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत में भी समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग मिलकर ऐसी सख्त गाइडलाइन तैयार करें, जिसमें यह प्रावधान हो कि चुनावी घोषणाओं से जुड़ा खर्च या तो स्पष्ट बजटीय प्रावधान के तहत हो या फिर राजनीतिक दल अपने निजी या घोषित फंड से उसका वहन करें, ताकि करदाताओं के धन का उपयोग केवल वोट बटोरने के लिए न हो।

यह भी तथ्य है कि वर्तमान वैश्विक तनाव और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के दौर में भारत को रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर अधिक निवेश की आवश्यकता है, लेकिन बढ़ता कर्ज इस क्षमता को सीमित कर रहा है। यदि वही धन कौशल विकास, सूक्ष्म उद्यमों, स्टार्टअप, स्वरोजगार और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने में लगाया जाए तो लोग स्थायी आय के साधन विकसित कर सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बन सकते हैं। इसलिए लोकलुभावनवाद और जनकल्याण के बीच स्पष्ट रेखा खींचना अब अनिवार्य हो गया है, ताकि लोकतंत्र मजबूत भी रहे और अर्थव्यवस्था जिम्मेदार रास्ते पर भी आगे बढ़े।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

—सम्पादक

बालिका विकास के बन्द दरवाजे खोलने का समय



ललित गर्गी पटपटगंज, दिल्ली-92

राष्ट्रीय बालिका दिवस बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सर्शक करण के लिए जागरूकता बढ़ाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का दिन है, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई, जिसके माध्यम से बालिकाओं की तस्वीर बदल रही है, जहाँ अब वे शिक्षा, खेल और नेतृत्व में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या और कुपोषण जैसी चुनौतियां अभी भी हैं, जिन्हें 'बेटी बचाओ, बेटी

पढ़ाओ' जैसी योजनाओं और कानूनों से दूर करने का प्रयास जारी है, जिससे वे समाज का गौरव और प्रतिष्ठा का चेहरा बन सकें। इस दिवस का उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना, लैंगिक भेदभाव को कम करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व पर जोर देना है। बालिकाएं अब विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा और नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। समाज में बेटियों के प्रति सोच में बदलाव आया है। कानूनी उपाय जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम, पोसको अधिनियम और सरकारी योजनाएं जैसे मिशन वास्तव्य, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन आदि बालिकाओं के कल्याण के लिए काम कर रही हैं। इन सबके बावजूद आज भी बालिकाएं शोषण एवं भेदभाव का शिकार हैं। बालिका लिंगानुपात में भले ही सुधार हुआ है, लेकिन बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाएँ अभी भी मौजूद हैं। बालिकाओं में एनीमिया और कम वजन जैसी पोषण संबंधी समस्याएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। पितृसत्तात्मक मानसिकता को खत्म करने और बालिकाओं को समान अवसर देने की आवश्यकता है। आजादी के अमृत काल



में भारत स्वयं को एक नए आत्मविश्वास, नई आकांक्षाओं और नए संकल्पों के साथ गे रहा है। इस परिवर्तनशील भारत की सबसे मजबूत आधारशिला यदि कोई है, तो वह है— बालिका। राष्ट्रीय बालिका दिवस आत्ममंथन का अवसर है कि आज हमारी बालिकाएं किस दश में हैं, किस दश में वे रही हैं और समाज उनके लिए कैसा भविष्य कर रहा है। यह भी प्रश्न है कि क्या हम वास्तव में उस भारत का निर्माण कर पा रहे हैं, जहां बालिका जन्म से ही बोझ नहीं, बल्कि भविष्य की निर्माता मानी जाए। दोनों हथ एक साथ को चरितार्थ करते हुए पुरुष एवं नारी दोनों की शक्ति से नया भारत निर्मित हो। पिछले कुछ दशकों में बालिकाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ी है, खेल, विज्ञान, प्रशासन, राजनीति और उद्यमिता में बालिकाओं और महिलाओं

ने असाधारण उपलब्धियां अर्जित की हैं। आज ग्रामीण भारत की बेटियां भी अंतरिक्ष विज्ञान, स्टार्टअप, सेना और सिविल सेवाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। यह परिवर्तन संकेत देता है कि आजादी के अमृत काल में महिलाओं और बालिकाओं की भूमिका केवल सहभागी नहीं, बल्कि नेतृत्वकारी होगी और यही राष्ट्र के सर्वोच्च शिखर की ओर ले जाने वाली शक्ति बनेगी। लेकिन इस उजली तस्वीर के समानांतर एक कड़वा यथार्थ भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज भी बालिकाओं और महिलाओं के विरुद्ध अपराध, शोषण, यौन हिंसा, घरेलू अत्याचार, बाल विवाह और साइबर उत्पीड़न जैसी घटनाएं समाज की संवेदनशीलता पर प्रसन्नचिह्न लगाती हैं। बलात्कार और हिंसा की घटनाएं केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं हैं, वे हमारी सामूहिक मानसिकता की विफलता का परिणाम हैं। जब एक बच्ची की सुरक्षा घर, स्कूल, सड़क और डिजिटल दुनिया—कहीं भी सुनिश्चित नहीं होती, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि विकास के दावे अशुभ हैं। नए भारत, विकसित भारत और समता-मूलक भारत की परिकल्पना में प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी की सोच का केंद्रबिंदु नारी-शक्ति और विशेषकर बालिकाओं का सर्शकिकरण है। उनका दृष्टिकोण केवल कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक मानसिकता के रूपांतरण का आह्वान करता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी अनेक योजनाओं ने बालिका को बोझ नहीं, बल्कि राष्ट्र की पूंजी के रूप में देखने की दृष्टि विकसित की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, डिजिटल सर्शकिकरण और सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं ने बालिकाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोले हैं। प्रधानमंत्री का यह स्पष्ट संदेश है कि जब तक बालिका शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर नहीं होगी, तब तक विकसित भारत का सपना अधूरा रहेगा। उनकी व्यापक सोच बालिका को केवल संरक्षण की वस्तु नहीं, बल्कि नेतृत्व, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की सक्रिय सहभागी मानती है। यही कारण है कि आज की बालिकाएं आत्मविश्वास के साथ विज्ञान, खेल, प्रशासन और उद्यमिता में आगे बढ़ रही हैं और आने वाला भारत नारी-शक्ति के नेतृत्व में संतुलित, समतामूलक और शक्ति राष्ट्र के रूप में उभरता दिखाई देता है।

अंबिकापुर सद्दा किंग दीप सिन्हा के घर छापेमारी...बेनामी संपत्ति और नकदी बरामद

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 22 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अवैध सट्टेबाजी के सिंडिकेट को ध्वस्त करने की दिशा में सरगुजा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। शहर के कथित 'सद्दा किंग' दीप सिन्हा की दो दिनों की पुलिस रिमांड आज समाप्त हो रही है, लेकिन इन 48 घंटों में पुलिस ने सट्टे के इस काले साम्राज्य की कई परतें खोल दी हैं। रिमांड के दौरान हुई गहन पूछताछ में दीप सिन्हा ने अपने नेटवर्क और सट्टेबाजी के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़े कई चौकाने वाले राज उगले हैं। पुलिस इस समय सट्टे के उस डिजिटल फुटपिंट को ट्रेक कर रही है, जिसके जरिए करोड़ों रुपये का हेरफेर किया गया था।

ताला तोड़कर अंदर घुसी पुलिस

शनिवार को पुलिस की एक विशेष टीम आरोपी दीप सिन्हा को लेकर सतीपारा स्थित उसके आलीशान आवास पर पहुंची। पुलिस के आने की भनक लगते ही घर के सभी सदस्य ताला लगाकर पहले ही फरार हो चुके थे। कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने और प्रवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद, पुलिस ने घर का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया। घंटों



बेनामी संपत्तियों का लगा अंबार, करोड़ों के निवेश के मिले पुरख्ता दस्तावेज

तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ जैकपॉट लगा है। दीप सिन्हा के घर से भारी मात्रा में नकदी के अलावा जमीन-जायदाद से जुड़े कई संदिग्ध कागजात बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि दीप सिन्हा ने क्रिकेट सट्टे से होने वाली काली कमाई को रियल एस्टेट और बेनामी संपत्तियों में निवेश किया था। जब्त किए गए दस्तावेजों में कई ऐसी जमीनों के कागजात हैं, जो दीप के करीबियों और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदे गए थे। पुलिस अब इन बेनामी संपत्तियों को अटैच करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है।

चली इस सचन तलाशी अभियान के दौरान घर के कोने-कोने को खंगाला गया। पुलिस को शक था कि सट्टे की अवैध कमाई से जुड़े सबूत और नकदी घर के भीतर छिपाई गई हो सकती है।

पुणे एयरपोर्ट से हुई थी नाटकीय गिरफ्तारी : बता दें कि दीप सिन्हा की गिरफ्तारी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। चार दिन पहले पुलिस ने एक गुप्त सूचना के



आधार पर उसे पुणे एयरपोर्ट के बाहर से घेराबंदी कर दबोचा था। दीप सिन्हा केवल अंबिकापुर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट सट्टे का कारोबार संचालित कर रहा था। वह आधुनिक ऐप्स और वेबसाइट्स के जरिए सट्टे का अवैध बाजार चलाता था। प्रारंभिक जांच में करोड़ों रुपये के बेनामी लेन-देन के प्रमाण मिले हैं, जो संकेत देते हैं कि इस नेटवर्क में कई बड़े सफेदपोश लोग भी शामिल हो सकते हैं।

फिर से रिमांड मांगने की तैयारी में जुटी पुलिस : दीप सिन्हा की मौजूदा रिमांड

अवधि समाप्त होने पर पुलिस उसे पुनः न्यायालय में पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में मिले नए सुरागों और बरामद दस्तावेजों के सत्यापन के लिए पुलिस अदालत से दीप की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। जांच अधिकारियों का कहना है कि अभी केवल एक छोटे हिस्से का पर्दाफाश हुआ है, सट्टे की इस चैन में कई बुकी और एजेंट अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अंबिकापुर पुलिस अब इन फरार आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

सद्दा प्रकरण में फरार आरोपी को मदद, दो पर अपराध दर्ज

थाना कोतवाली पुलिस ने जुआ प्रतिषेध अधिनियम एवं आईटी एक्ट से जुड़े मामलों की विवेचना के दौरान फरार आरोपी आयुष सिन्हा उर्फ दीप सिन्हा के मोबाइल से मिले वाट्सएप चैट और फोन-पे ट्रांजैक्शन के आधार पर उसके साले संतोष कश्यप एवं मोन्टी सोनी उर्फ मुरलीधर सोनी के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी आयुष सिन्हा के मोबाइल में उपलब्ध वाट्सएप चैट से यह सामने आया कि संतोष कश्यप और मोन्टी सोनी लगातार उसके संपर्क में थे। दोनों ने फोन-पे के माध्यम से 50-50 हजार रुपये एटीएम के जरिए फरार आरोपी आयुष सिन्हा के खाने में जमा कराए। जांच में यह भी पाया गया कि आयुष सिन्हा ऑनलाइन सद्दा प्रकरण में मुख्य आरोपी है और फरार चल रहा है। इसके बावजूद संतोष कश्यप ने 17 नवंबर 2025 को आयुष सिन्हा के खाने में 2 लाख 10 हजार रुपये जमा कराए। पुलिस ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए शासन की ओर से विवेचना कर रहे निरीक्षक शशिकांत की रिपोर्ट पर संतोष कश्यप एवं मोन्टी सोनी के विरुद्ध फरार आरोपी को छिपाने, संश्रय देने और लगातार मदद करने के आरोप में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण एक बार फिर ठंड की वापसी



वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण

वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण उत्तर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ठंड की वापसी देखी जा रही है। दो दिन पूर्व न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के ऊपर चला गया था। इस लिए लोग शीतलहर से राहत महसूस कर रहे थे। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण बुधवार की रात का न्यूनतम तापमान नीचे गिरकर 6.3 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक का मानना है कि विशोभ का असर आने वाले दो से तीन दिनों तक रहेगा। इसके बाद पुनः तापमान में वृद्धि दर्ज की जा सकती है। इस वर्ष उत्तर छत्तीसगढ़ में कड़ुके की ठंड पड़ी है। लगातार 49 दिनों तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा है। पूरा सरगुजा संभाग शीतलहर की चपेट में था। दो से तीन दिन पूर्व धीरे-धीरे ठंड से राहत मिली थी। न्यूनतम तापमान बढ़ कर 10 डिग्री से ऊपर पहुंच गया था। वहीं वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण एक बार फिर से ठंड की वापसी हुई है। न्यूनतम तापमान गिरने से रातें ठंड हो गई हैं। जबकि मंगलवार को न्यूनतम तापमान बढ़कर 11 डिग्री पहुंच गया था।

प्रवेश कर रही सर्द हवाएं

मौसम वैज्ञानिक एएम भट्ट के अनुसार पश्चिमी विशोभ के सक्रिय होने से न्यूनतम व अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई थी। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण फिर से सर्द हवाओं का प्रवेश शुरू हो गया है। इस लिए तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसका अवसर आने वाले दो से तीन दिनों तक रहने की उम्मीद है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर खत्म होते ही फिर से तापमान में वृद्धि दर्ज की जा सकती है।

रेलवे की मण्डल स्तरीय बैठक में सांसद चिंतामणि महाराज ने क्षेत्रहित में रखी कई मांगें



संवाददाता-

अम्बिकापुर, 22 जनवरी 2026 (घटती-घटना)। सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर में आयोजित मंडल स्तरीय बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री व बिलासपुर सांसद श्री तोखन साहू और समस्त माननीय सांसदों की उपस्थिति में सहभागिता की। बैठक के दौरान क्षेत्र की जनता, किसानों एवं व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से रखते हुए रेलवे प्रशासन के समक्ष निम्नलिखित महत्वपूर्ण मांगें एवं प्रस्ताव मजबूती से रखे। अंबिकापुर-दिल्ली (निजामुद्दीन) रेल सेवा का सप्ताह में न्यूनतम दो दिन नियमित संचालन सुनिश्चित किए जाने की मांग, जिससे सरगुजा क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी से बेहतर रेल संपर्क मिल सके। कमलपुर रेलवे स्टेशन पर अंबिकापुर-दुर्ग रेलगाड़ी को उल्टाव प्रदान करने का निवेदन, जिससे क्षेत्र के सड़की उत्पादक किसानों एवं स्थानीय व्यापारियों को सीधा लाभ प्राप्त हो। विश्रामपुर एवं सूरजपुर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म तथा शेड की लंबाई बढ़ाने की मांग। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म निर्माण कार्य विगत पाँच माह से लंबित रहने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्य में तत्काल तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश देने की मांग। शहडोल-नागपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन अंबिकापुर से प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव, जिससे सरगुजा अंचल को मध्य भारत से सीधा रेल संपर्क मिल सके। अंबिकापुर-रायपुर इंटरसिटी ट्रेन के शीघ्र नियमित परिचालन की मांग। पूर्व की सभी बैठकों में हुई चर्चाओं, लिए गए निर्णयों एवं उनके क्रियान्वयन की स्थिति पर आधारित विंदुवार कार्यवाही विवरण उपलब्ध कराने का स्पष्ट आग्रह। सांसद सरगुजा श्री चिंतामणि महाराज ने पूर्व बैठकों में दिए गए निर्देशों का अपेक्षित अनुपालन न होने पर कड़ी असंतुष्टि व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि यदि भविष्य में स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आगामी बैठकों का बहिष्कार करने पर विचार किया जाएगा। इस अवसर पर रेलवे महाप्रबंधक द्वारा इस स्थिति पर खेद व्यक्त करते हुए सभी लंबित विषयों के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया।

युवा उड़ान कार्यक्रम में युवाओं को मिला प्रेरणा और मार्गदर्शन पद्मश्री आनंद कुमार और लेखक नीलोत्पल मृणाल ने साझा किए सफलता के मंत्र

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 22 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

जिले में कला केंद्र मैदान अम्बिकापुर में आयोजित युवा उड़ान कार्यक्रम युवाओं के लिए प्रेरणा, मार्गदर्शन और आत्मविश्वास का सशक्त मंच साबित हुआ। कार्यक्रम में देश के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं सुपर 30 के संस्थापक पद्मश्री श्री आनंद कुमार तथा विश्वविख्यात लेखक श्री नीलोत्पल मृणाल ने युवाओं को सफलता, संघर्ष और जीवन के मूल्यों पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि सरगुजा के युवाओं के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि उन्हें आनंद कुमार और नीलोत्पल मृणाल जैसे प्रेरणादायी व्यक्तित्वों को सुनने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उड़ान पंखों से नहीं, बल्कि मेहनत से मिलती है। हमारी चाह और संकल्प ही हमें लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। युवाओं को लक्ष्य निर्धारित कर ऊंची उड़ान का हैसिया रखना चाहिए। कार्यक्रम में लुण्ठ विधायक श्री प्रबोध मिश्र ने कहा कि यह आयोजन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्वविजय सिंह तोमर ने युवाओं से मंच से प्राप्त विचारों को ध्यानपूर्वक सुनकर उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने कहा कि जिले के युवाओं को आज महान व्यक्तित्वों के अनुभवों और दृष्टिकोण को जानने का अवसर मिला है।



उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन की चुनौतियों को साझा करते हुए युवाओं को कठिन परिस्थितियों का सामना कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

परीक्षाओं की तैयारी और सफलता का दिए मंत्र

कार्यक्रम में सुपर 30 के संस्थापक श्री आनंद कुमार ने युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के महत्वपूर्ण टिप्स और सफलता के मंत्र बताए। उन्होंने कहा कि यहां बैठे हर बच्चा नायाब है और सभी में अद्भुत हुनर है। आवश्यकता है उस ताकत को पहचानने की और दुनिया में बेहतर कार्य कर मिसाल कायम करने की। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए जरूरी है, कि जिस विषय में सफल होना है, उसी विषय को लेकर पूरी निष्ठा के साथ जीवन जिया जाए और किसी भी अन्य चीज को बीच में आने न दिया जाए। विषय समझने

में कठिनाई आने पर हार मानने के बजाय निरंतर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लगातार मेहनत से सफलता अवश्य मिलती है। श्री आनंद कुमार ने कहा कि पढ़ाई को बोझ नहीं, बल्कि रोमांचक बनाना चाहिए। आज इंटरनेट जैसे आधुनिक संसाधनों में हर समस्या का समाधान उपलब्ध है, आवश्यकता केवल सही दिशा में प्रयास करने की है। उन्होंने अपने करियर के संघर्षों और जीवने को साझा करने को युवाओं को चुनौतियों को साझा करते हुए कहा कि असुविधाएं मिलने पर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि धारा के विपरीत चलकर भी पथरों को तोड़ते हुए आगे बढ़ा जा सकता है।

उन्होंने युवाओं को सफलता के चार मंत्र भी बताए। उन्होंने कहा कि पहला मंत्र प्रबल प्रयास - जब तक सफलता न मिले, प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरा मंत्र सकरात्मक सोच-जो निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तीसरा मंत्र अथक परिश्रम - बिना रुके और बिना थके मेहनत



डर से डरने के बजाए संघर्ष की आग में तपना जरूरी

कार्यक्रम में शामिल विश्वविख्यात लेखक श्री नीलोत्पल मृणाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का युवा ही छत्तीसगढ़ की तकदीर है और एक परीक्षा किसी की तकदीर का फैसला नहीं करती। उन्होंने कहा कि डर से डरने के बजाय संघर्ष की आग में तपना होगा, तभी वास्तविक सफलता प्राप्त होगी। उन्होंने युवाओं को चेताया कि डिप्रेशन को पैशन न बनाएं, क्योंकि डिप्रेशन और पैशन एक साथ नहीं चल सकते। यदि भीतर आगे बढ़ने का पैशन है, तो सफलता निश्चित है। श्री मृणाल ने कहा कि संघर्ष हर व्यक्ति के आसपास मौजूद है और इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं होना चाहिए। उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि दूसरों की आकांक्षाओं को अपना बोझ बनाकर न छोड़ें, बल्कि स्वयं यह निर्णय लें कि उन्हें किस क्षेत्र में जाना है और उसी लक्ष्य पर अडिग रहें। चाहे कोई भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न आए, अपने निर्णय से विचलित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मंच युवाओं में चेतना जगाने के उद्देश्य से है। यदि युवा दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें, तो आने वाला कल उन्हीं का होगा और वहीं भविष्य में इतिहास रचेंगे।

करना ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। चौथा मंत्र असीम धैर्य - यदि प्रयास तुरंत सफल न हों तो निराश नहीं होना चाहिए। धैर्य रखते हुए परिश्रम निरंतर करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। पढ़ाई को

लेकर बच्चों में बढ़ते डिप्रेशन पर उन्होंने कहा कि इसमें माता-पिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।

अवैध धान भंडारण पर छापा, भाजपा नेता ने अफसरों को दी धमकी कार्रवाई का वीडियो वायरल, करीब 5 लाख का धान जब्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 22 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

सीतापुर में भाजपा नेता के निवास पर अवैध धान भंडारण की सूचना पर प्रशासनिक टीम की छापामार कार्रवाई के दौरान विवाद की स्थिति बन गई। नायब तहसीलदार के नेतृत्व में पहुंची टीम को भाजपा नेता व अधिकारता ने खुलेआम धमकी दी। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

प्रशासन को सूचना मिली थी कि सीतापुर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं अधिकारता सुनील गुप्ता के निवास पर अवैध रूप से धान का भंडारण किया गया है। बताया गया कि बुधवार रात दो ट्रकों में भरकर अवैध धान उनके घर पहुंचाया गया। सूचना के आधार पर



गुरुवार दोपहर नायब तहसीलदार तुषार मानिक और राजेश यादव के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम भाजपा नेता के निवास पर छापामार कार्रवाई करने पहुंची। इसी दौरान भाजपा नेता मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का विरोध करते हुए अधिकारियों को धमकाने लगे। 'जानकारों' लेकर जब्ती बनाए, नहीं तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा। आपके जैसे पांच लोग रोज आते हैं। बड़े अधिकारी, कलेक्टर और आईएएस तक हमारे पास आते हैं। जब फंसते हैं तो हमारे पास ही आते हैं। 'इस दौरान भाजपा नेता लगातार अधिकारियों को खरी-खोटी सुनाते रहे। भाजपा नेता की भाषा पर आपत्ति जताते हुए नायब

तहसीलदार ने उन्हें ढंग से बात करने को कहा। इस पर भाजपा नेता और उग्र हो गए। उन्होंने कहा, 'मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं जानबूझकर यहां आया हूँ। 2-3 लाख का माल ही जाएगा न, करोड़पति थोड़ी न बन जाऊंगा। लेकिन इस तरह करोगे तो बाजा बजा दूंगा, चाहे कभी भी रहे। 'कार्रवाई का विरोध करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि जब्ती नहीं बनने देंगे और अधिकारियों को शटर के भीतर बंद करने की भी कोशिश की। हालांकि प्रशासनिक टीम ने संयम बरतते हुए पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत धान की जब्ती की कार्रवाई पूरी की। प्रशासन के अनुसार, जब्त धान की कीमत करीब 5 लाख रुपये आंकी जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

बालगृह के कर्मचारियों को सेवा समाप्त होने का डर, कलेक्टर को ज्ञापन



-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 22 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत एनजीओ द्वारा संचालित बालगृह में कार्यरत कर्मचारियों ने सोमवार को अपनी सेवाएं समाप्त किए जाने की आशंका को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से सेवाएं यथावत रखने की मांग की है। कर्मचारियों ने बताया कि वे

बीते कई वर्षों से अनाथ, निराश्रित एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की सेवा पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते आ रहे हैं। उन्होंने कोरोना महामारी काल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस कठिन समय में, जब पूरा देश भय और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था, तब भी उन्होंने अपने परिवारों से दूर रहकर बालगृह में बच्चों की देखभाल की। कर्मचारियों के अनुसार, कोरोना काल में कई महीनों

तक वे बालगृह परिसर में ही रहकर बच्चों की सुखा, भोजन, इलाज, शिक्षा और मानसिक देखभाल की जिम्मेदारी निभाते रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ा। अब कर्मचारियों ने आशंका जताई है कि उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं, जिससे उनके परिवारों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। साथ ही, इसका सीधा असर

बालगृह में रह रहे बच्चों की देखरेख और व्यवस्थाओं पर भी पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान कर्मचारी इस कार्य में प्रशिक्षित और अनुभवी हैं। कर्मचारियों ने कलेक्टर से मांग की कि उनके अनुभव, सेवा और त्याग को ध्यान में रखते हुए एनजीओ संचालित बालगृहों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को यथावत सेवा में रखा जाए, ताकि बच्चों की देखभाल व्यवस्था प्रभावित न हो। इस दौरान बड़ी संख्या में बालगृह कर्मचारी उपस्थित रहे।

सूरजपुर में 11 करोड़ का धान खरीदी घोटाला उजागर, 37 हजार क्विंटल धान गायब

धान खरीदी में महाघोटाला, सूरजपुर के 10 से अधिक उपार्जन केंद्रों में भारी कमी

37,734 क्विंटल धान की कमी से हड़कंप, प्रशासन एक्शन मोड में

धान खरीदी घोटाले पर प्रशासन सख्त, करोड़ों के गबन की जांच तेज

धान खरीदी घोटाले में एफआईआर की तैयारी, 11.69 करोड़ की अनियमितता उजागर

भौतिक सत्यापन में खुली पोल, सूरजपुर में हजारों क्विंटल धान गायब

धान खरीदी में बड़ा खेल, नोटिस से आगे बढ़ी जांच

किसानों के धान में घोटाला, 11 करोड़ का स्टॉक गायब

सूरजपुर में धान खरीदी घोटाला, 37 हजार क्विंटल धान कम

दैनिक घटती-घटना की खबरों के बाद प्रशासन एक्शन मोड में, एफआईआर की तैयारी



सूरजपुर धान खरीदी घोटाला
11 करोड़ का खेल!



धान खरीदी घोटाला : जांच के बाद भी वही जिम्मेदार, कमी 'मैनेज' करने की खुली छूट



-ओकर पाण्डेय-
सूरजपुर, 22 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

सूरजपुर जिले में धान खरीदी व्यवस्था से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है, जिले के विभिन्न धान उपार्जन केंद्रों में कराए गए भौतिक सत्यापन के दौरान 37,734 क्विंटल धान की भारी कमी पाई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 11 करोड़ 69 लाख 75 हजार 400 रुपये आंकी गई है। यह मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि व्यवस्थित भ्रष्टाचार और शासकीय राशि के दुरुपयोग की ओर सीधा संकेत करता है, दैनिक घटती-घटना में लगातार प्रकाशित खबरों के बाद प्रशासन हरकत में आया और जिले में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया।

कैसे खुला पूरा मामला

पिछले कई महीनों से सूरजपुर जिले के धान उपार्जन केंद्रों से रिकॉर्ड में खरीदी दिखना, भुगतान हो जाना, लेकिन गोदामों में धान नहीं मिलना जैसी शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं, दैनिक घटती-घटना द्वारा इन अनियमितताओं को प्रमुखता से उजागर किए जाने के बाद उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला सूरजपुर के निर्देश पर धान उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन कराया गया।

नोटिस काफी नहीं, अब कार्रवाई जरूरी

प्रशासन द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करना आवश्यक कदम था, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, इससे पहले भी प्रदेश में कई बार ऐसे घोटाले सामने आए, जिनका अंत नोटिस और फाइलों तक सीमित रह गया। यदि 11 करोड़ रुपये की अनियमितता पर केवल स्पष्टीकरण लेकर मामला समाप्त कर दिया गया, तो यह न केवल किसानों बल्कि ईमानदार अधिकारियों के साथ भी अन्याय होगा, अब समय आ गया है कि दोषियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय हो, राशि की शत-प्रतिशत वसूली हो और आवश्यक होने पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए।

10 से अधिक केंद्रों में जांच 8 केंद्रों के ठोस आंकड़े सामने-

प्रशासन द्वारा अब तक 10 से अधिक धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया जा चुका है, इनमें से 8 केंद्रों में भारी मात्रा में धान की कमी के ठोस आंकड़े उपलब्ध हुए हैं, 2 केंद्रों के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हो सके हैं।

सबसे बड़ा सवाल - धान गया कहाँ?

यह सवाल अब पूरे जिले में गूंज रहा है कि जब धान खरीदा गया, किसानों को भुगतान किया गया, शासन ने राशि जारी की, तो फिर इतना बड़ा स्टॉक आखिर गायब कैसे हो गया? रिकॉर्ड में

मौजूद धान और गोदाम में मौजूद वास्तविक स्टॉक के बीच यह अंतर सीधे तौर पर घोटाले की पुष्टि करता है।

पांच समितियों को कार्रण बताओ नोटिस

भौतिक सत्यापन के बाद प्रशासन ने 5 समितियों के प्रबंधकों एवं धान खरीदी प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, शेष केंद्रों में जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे, कुछ नोटिसों की जवाब देने की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब तक उनकी आगे की कार्रवाई सार्वजनिक नहीं की गई है।

प्रशासन की स्पष्ट चेतावनी

नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया तो, एफआईआर दर्ज की जाएगी, वित्तीय नुकसान की वसूली की जाएगी, निलंबन एवं सेवा समाप्ति की कार्रवाई संभव है, कार्रवाई निम्न कानूनों के अंतर्गत होगी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, नियम 1962 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं सेवा नियम 2018

प्रशासन अब सख्त रुख में...

सूत्रों के अनुसार प्रशासन यह मान रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में कमी, बिना संगठित नेटवर्क के संभव नहीं, इसमें खरीदी प्रभारी, समिति

धान की कमी के चौकाने वाले आंकड़े

उपार्जन केंद्र	धान की कमी (क्विंटल)
चंदौर	818
लटोरी	4,367.60
सोनपुर बंजा	4,350
शिवप्रसाद नगर	5,552
उमेश्वरपुर	7,036.40
सूरजपुर	6,610.40
टुकुंडांड	6,412.80
सावरवां	2,588
कुल कमी	37,734 क्विंटल धान
अनुमानित मूल्य	11.69 करोड़
नोटिस प्राप्त अधिकारी	

विकास जायसवाल - टुकुंडांड
मोहम्मद रिजवान अंसारी - सावरवां
ठाकुर सिंह मरावी - उमेश्वरपुर
साधना कुशवाह - शिवप्रसाद नगर
मोहन राजवाड़े - सूरजपुर

प्रबंधन, परिवहन व स्टोरेज स्तर तक की भूमिका की जांच की जा रही है, जल्द ही विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट, परिवहन चालान मिलान, टोकन व रिकॉर्ड सत्यापन, सीसीटीवी व लॉजिस्टिक डेटा के आधार पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा सकते हैं।

किसानों में तोष, पारदर्शिता की मांग

स्थानीय किसानों और समाजिक संगठनों ने कहा कि धान खरीदी में भ्रष्टाचार का सीधा असर किसानों पर पड़ता है, भुगतान, वजन और रिकॉर्ड पूरी तरह पारदर्शी हों, दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं न हों।

पत्रकारिता का असर

यह पूरा मामला एक बार फिर साबित करता है कि जिम्मेदार पत्रकारिता ही भ्रष्टाचार को उजागर कर सकती है, दैनिक घटती-घटना में लगातार प्रकाशित खबरों के बाद ही प्रशासन सक्रिय हुआ, सत्यापन शुरू हुआ और करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश संभव हो पाया।

अब क्यों कण? अब जिले को कलकत्ता के फिरोज़ दान पर दिखे हैं कि...

- क्या वास्तव में एफआईआर दर्ज होगी?
- क्या दोषियों से 11 करोड़ से अधिक की वसूली होगी?
- या मामला एक बार फिर कागजों में सिमट जाएगा?

धान खरीदी व्यवस्था किसानों की आय और राज्य की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी है। ऐसे में यह प्रकरण केवल आर्थिक नहीं बल्कि जनहित और विश्वास का मामला बन चुका है। (क्रमशः - जांच जारी है, आगे और खुलासा संभव है)



एसडीएम प्रतापपुर ने सीएचसी प्रतापपुर का किया निरीक्षण

स्वास्थ्य सुविधाओं, साफ-सफाई व मूलभूत व्यवस्थाओं का लिया जायजा

-संवाददाता-
सूरजपुर, 22 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) प्रतापपुर द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) प्रतापपुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं सहित साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, भवन की स्थिति एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया गया, निरीक्षण के समय बीएमओ प्रतापपुर, एई इलेक्ट्रिक, एसडीओ लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), एसडीओ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) एवं एसडीओ आर्इएस उपस्थित रहे।

व्यवस्थाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश

एसडीएम ने अस्पताल परिसर में उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं, ओपीडी, वाई.टी. दवा वितरण कक्ष, स्वच्छता व्यवस्था तथा बिजली-पानी की स्थिति की जानकारी संबंधित अधिकारियों से प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आवश्यक सुधार कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं : एसडीएम

निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने स्पष्ट कहा कि आम नागरिकों को बेहतर और सुचारु स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उन्होंने निर्देश दिए कि निरीक्षण के दौरान चिन्हित कमियों को शीघ्र दूर किया जाए तथा सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

जल्द सुधार के निर्देश

एसडीएम ने संबंधित विभागों को अस्पताल में आवश्यक मरम्मत, विद्युत व्यवस्था सुधार, पेयजल आपूर्ति को सुचारु करने एवं स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए समय-सीमा तय कर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए, निरीक्षण से स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर उपचार सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

घटिया सड़क निर्माण की शिकायत पर सीएम ने दिए सख्त निर्देश

विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : सीएम साय

-संवाददाता-
सूरजपुर, 22 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सूरजपुर आगमन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. शुक्ला के निवास पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ सौजन्य मुलाकात आयोजित की गई, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और आम नागरिकों से सीधे संवाद किया। बैठक के दौरान रामानुजगंजर क्षेत्र से जुड़े एक वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा कराए जा रहे लगभग 50 करोड़ रुपये की सड़क निर्माण योजना में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत मुख्यमंत्री के समक्ष रखी।

घटिया गुणवत्ता को लेकर गंभीर आरोप : वरिष्ठ कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि रामानुजगंजर नगर क्षेत्र में



निर्माणधीन सीसी रोड की गुणवत्ता अत्यंत खराब है, सड़क निर्माण इस कदर कमजोर किया जा रहा है कि निर्माण पूर्ण होने से पहले ही गिट्टियां उखड़ने लगी हैं, शिकायत में यह भी बताया गया कि भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने तक सड़क को सही दर्शाने के उद्देश्य से

डामरकरण और इमर्शन किया जा रहा है, जिससे वास्तविक गुणवत्ता छिपाई जा सके।
मुख्यमंत्री ने जताई कड़ी नाराजगी : मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी स्थिति में घटिया निर्माण कार्य

बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्होंने निर्देश दिए कि जहां भी गुणवत्ताहीन कार्य पाए जाएं, वहां निर्माण कार्य तत्काल बंद कराया जाए तथा संबंधित विधायक एवं जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत दर्ज कराई जाए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पैसा सरकार का नहीं, जनता की गाढ़ी कमाई का है। यह संपत्ति जनता की है और इसका लाभ भी जनता को ही मिलना चाहिए। इसलिए विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जनता में बढ़ा भरोसा : मुख्यमंत्री के सख्त रुख और स्पष्ट निर्देश के बाद क्षेत्रवासियों में गुणवत्तापूर्ण विकास कार्यों को लेकर विश्वास बढ़ा है, लोगों को उम्मीद है कि अब सड़क, भवन और अन्य निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी, स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और विकास कार्य वास्तव में जनता के हित में पूरे होंगे।

कांग्रेस के अल्टीमेटम के बाद शुरू हुआ फेस केवाईसी नेता प्रतिपक्ष ने जताया आभार, हजारों वंचित होंगे लाभान्वित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 22 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

फिंगर केवाईसी विफलता के कारण राशन से वंचित किए गए हितग्राहियों के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों द्वारा कलेक्टर को दिए गए अल्टीमेटम पर जिला प्रशासन ने त्वरित

कार्यवाही करते हुए फेस केवाईसी की सुविधा शुरू कर दी है। जिला खाद्य अधिकारी ने नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद को फोन पर जानकारी दी कि तत्काल प्रभाव से फेस केवाईसी लागू कर दी गई है। अब वे सभी हितग्राही जिनका नाम फिंगर केवाईसी न होने के कारण राशन कार्ड से कट गया था, फेस केवाईसी करवाकर पुनः राशन प्राप्त

कर सकेंगे। इस फेसले से विशेष रूप से बुजुर्गों, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा मेहनतकश श्रमिकों को राहत मिलेगी, जिनकी उंगलियों की पहचान मशीनों में नहीं हो पा रही थी। शफी अहमद ने बताया कि प्रभावित हितग्राही अपनी नजदीकी उचित मूल्य दुकान या निर्धारित केंद्र पर जाकर फेस केवाईसी करवा सकते हैं। उन्होंने

इस त्वरित निर्णय के लिए जिला प्रशासन एवं खाद्य विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया। कांग्रेस पार्षद दल ने जिले के सभी प्रभावित नागरिकों से अपील की कि वे फेस केवाईसी की सुविधा का लाभ लेकर राशन प्राप्त करें और किसी प्रकार की समस्या होने पर खाद्य विभाग अथवा अपने जनप्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं।



तहसीलदार
सूरजपुर
सील जिला मुरझापुर बहाग

भाजपा ने तीन मोर्चों की जिला कार्यसमिति घोषित की

युवा, किसान और अनुसूचित जनजाति मोर्चा को मिली नई टीम, संगठन विस्तार की दिशा में बड़ा कदम, जिले में पार्टी को मिलेगी नई ऊर्जा

-संवाददाता-
कोरिया, 22 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक मजबूती की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा एवं किसान मोर्चा की जिला कार्यसमिति एवं मंडल पदाधिकारियों की सूची आधिकारिक रूप से जारी कर दी है।

तीनों मोर्चों की नई टीम का गठन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री (संगठन)

पवन साय के मार्गदर्शन में तथा भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी की सहमति से संबंधित मोर्चा जिलाध्यक्षों द्वारा किया गया, पार्टी नेतृत्व ने विश्वास व्यक्त किया है कि इन नई कार्यसमितियों के माध्यम से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी और केंद्र-राज्य सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में युवाओं, किसानों और आदिवासी समाज की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित होगी।

संगठन को मिलेगी नई दिशा तीनों मोर्चों के जिलाध्यक्षों ने कहा कि...

नई कार्यसमिति पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगी

युवाओं, किसानों एवं आदिवासी समाज को संगठन से जोड़ेगी

केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाएगी...

आगामी चुनावी चुनौतियों के लिए संगठन को तैयार करेगी, नई नियुक्तियों के साथ भाजपा संगठन में उत्साह का माहौल है और जिले में पार्टी को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है...



भाजपा किसान मोर्चा की नवगठित जिला कार्यसमिति घोषित

शिवचरण साहू के नेतृत्व में संगठन को मिली नई मजबूती

किसान मोर्चा की जिला कार्यसमिति का गठन जिलाध्यक्ष शिवचरण साहू द्वारा किया गया, उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा किसानों के हितों की रक्षा, योजनाओं के प्रचार-प्रसार और संगठन विस्तार को प्राथमिकता देगा।

जिला पदाधिकारी

जिला उपाध्यक्ष- रितेश सिंह, दिलीप यादव, ईश्वर साहू, महेन्द्र साहू
जिला महामंत्री- जय चक्रधारी, प्रेमप्रकाश पाण्डेय
जिला मंत्री- आनंद राजवाड़े, विनोद राजवाड़े, सुनील दुबे, बसंत सिंह, सोना यादव
कोषाध्यक्ष - रामसागर तिवारी
मीडिया प्रभारी - अशोक यादव

किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष

बैकुण्ठपुर - प्रदीप कुमार राजवाड़े
चरचा - दिनेश कुमार पुरी
सलका - दिनेश चेरवा
कुड़ेली - बालकृष्ण द्विवेदी
पटना - अजीत राजवाड़े
बचरापोड़ी - हीरावन साहू
सोनहत - हरिश्चंद्र राजवाड़े



भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की जिला कार्यसमिति घोषित

अनुसूचित जनजाति मोर्चा की जिला कार्यसमिति की घोषणा जिलाध्यक्ष विमलचंद्र चेरवा द्वारा की गई, उन्होंने कहा कि नई टीम आदिवासी समाज के अधिकार, विकास और कल्याण योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए कार्य करेगी।

प्रमुख पदाधिकारी

जिला उपाध्यक्ष- रघुनाथ सिंह, समयलाल चेरवा (सहादुर), संतोष सिंह, जगदीश सिंह
जिला महामंत्री- कमलेश एक्का, राय सिंह
जिला मंत्री- देवलाल चेरवा, छत्रपाल सिंह, विश्वनाथ सिंह, लक्ष्मण नायक, उग्रसेन तिकी, नंदनी सिंह
कोषाध्यक्ष - अमरसाय
मीडिया प्रभारी - प्रीतम भगत

मंडल अध्यक्ष

बैकुण्ठपुर - महेन्द्र चेरवा
चरचा - लालचंद
सलका - महेन्द्र पैकरा
कुड़ेली - लहर साय
पटना - मंगल सिंह
बचरापोड़ी - राजेन्द्र सिरदार
सोनहत - मैन प्रताप सिंह



भाजयुमो की जिला कार्यसमिति घोषित

सतेन्द्र राजवाड़े के नेतृत्व में युवा मोर्चा को मिली नई टीम भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की जिला कार्यसमिति एवं मंडल अध्यक्ष-महामंत्री सूची जिलाध्यक्ष सतेन्द्र राजवाड़े द्वारा जारी की गई, उन्होंने कहा कि नई टीम युवाओं को संगठन से जोड़ने और राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ कार्य करेगी।

जिला पदाधिकारी

जिला उपाध्यक्ष- रमेश तिवारी, कमलेश साहू, राकेश खारवा, शुभम जायसवाल
जिला महामंत्री- मनोज साहू, सुश्री साक्षी सिंह
जिला मंत्री- प्रवेन्द्र सिंह, लल्लू यादव, दीपक कुशवाहा, उर्मिला पैकरा, मनीष साहू
कोषाध्यक्ष - अरुण राज कुर्
सह कोषाध्यक्ष - राहुल चौधरी, रणविजय सिंह
कार्यालय प्रमुख - संजय साहू
सह कार्यालय प्रमुख - आशीष गुप्ता
मीडिया प्रभारी - राजीव घोष
सह मीडिया प्रभारी - सुजय जैन, भगवान यादव
प्रशिक्षण प्रमुख - रवि राजवाड़े
आईटी सेल प्रभारी - शिवम सागर
सोशल मीडिया प्रभारी - रमेश राजपूत (विक्की)
(अन्य पदाधिकारियों व कार्यसमिति सदस्यों की सूची यथावत)

युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष-महामंत्री

बैकुण्ठपुर - अध्यक्ष विकास दुबे, महामंत्री भुनेश्वर राजवाड़े
चरचा - अध्यक्ष श्रीराम दुबे, महामंत्री कमलेश बघेल
सलका - अध्यक्ष शक्ति साहू, महामंत्री तेजप्रताप सिंह
कुड़ेली - अध्यक्ष मनोज यादव
पटना - अध्यक्ष जय राजवाड़े, महामंत्री कपिल कुशवाहा
बचरापोड़ी - अध्यक्ष प्यारे सिंह, महामंत्री विजय श्रीवास
सोनहत - अध्यक्ष दिलीप राजवाड़े, महामंत्री सोनू प्रजापति

शंकराचार्य को शाही स्नान से रोकना भाजपा का हिन्दू विरोधी चरित्र : शशि सिंह

शंकराचार्य का अपमान सनातन धर्म का अपमान - जिला कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया

प्रयागराज माघ मेले में संत पर प्रतिबंध, कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरा

40 वर्षों की परंपरा टूटी, शंकराचार्य को स्नान से रोके जाने पर कांग्रेस का आक्रोश



-संवाददाता-
सूरजपुर, 22 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शाही स्नान से रोके जाने एवं उनके साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी सूरजपुर ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे सनातन परंपरा पर सीधा प्रहार बताया है। उन्होंने कहा कि स्वयं को हिंदुओं का सबसे बड़ा हिस्सा बताने वाली भाजपा सरकार आज हिंदू संतों के अपमान पर उतर आई है। हालात इतने गंभीर हैं कि शंकराचार्य को अपनी सुरक्षा को लेकर भय की स्थिति बनी हुई है और वे पिछले 36 घंटे से अनशन पर बैठने को विवश हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक उनसे संवाद का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया।

समर्थकों के साथ दुर्व्यवहार, बाल पकड़कर घसीटने के आरोप

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि शंकराचार्य के शिष्यों एवं समर्थकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उन्हें बाल पकड़कर घसीटा गया, धक्का-मुक्की की गई और शंकराचार्य को उनकी पालकी तक ले जाने की अनुमति तक नहीं दी गई, उन्होंने सवाल उठाया कि जब धार्मिक आस्था के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा सत्ता में है, तो फिर संतों और साधुओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया जा रहा है।

सनातन परंपरा पर सीधा हमला

शशि सिंह ने कहा कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछले 40 वर्षों से लगातार शाही स्नान करते आ रहे हैं, यह पहली बार है जब उन्हें इस अखंड धार्मिक परंपरा से रोका गया है, उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या का शाही स्नान सदियों पुरानी सनातन परंपरा है, जिसे न तो मुगल शासकों ने रोका और न ही अंग्रेजों ने, लेकिन आज भाजपा सरकार ने इस परंपरा को तोड़ने का दुस्साहस किया है, उन्होंने आरोप लगाया कि शंकराचार्य को शाही स्नान से रोकना केवल एक संत का नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म का अपमान है।

सुरक्षा में दोहरा मापदंड : कांग्रेस

शशि सिंह ने कहा कि एक ओर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को जेड-प्लस सुरक्षा प्रदान की जाती है, वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य के अनुयायियों पर लाठीचार्ज और मारपीट की जाती है, उन्होंने तीखा सवाल करते हुए कहा क्या अब मोहन भागवत, शंकराचार्य से भी बड़े हो गए हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार संतों में भी पसंद-नापसंद की राजनीति कर रही है।

सरकार की आलोचना करना बना अपराध

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अपराध केवल इतना है कि वे सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, अयोध्या में आधे-अधूरे राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा पर आपत्ति जताते हैं, महाकुंभ की अव्यवस्थाओं को उजागर करते हैं, क्रोडिड काल में गंगा में बहती लाशों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सच बोलते हैं, इसी कारण भाजपा सरकार उन्हें दबावे और अपमानित करने पर आमादा है।

हिंदुत्व के नाम पर ढोंग कर रही भाजपा : कांग्रेस

शशि सिंह ने कहा कि भाजपा पिछले 12 वर्षों से केंद्र की सत्ता में रहते हुए हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती रही है, लेकिन जब वास्तविक सनातन परंपरा और संत समाज के सम्मान की बात आती है, तब उसका असली चेहरा सामने आ जाता है, उन्होंने कहा कि यह घटना साबित करती है कि भाजपा का हिंदुत्व केवल चुनावी मंचों और भाषणों तक सीमित है, जबकि धरातल पर संत, परंपरा और आस्था का अपमान किया जा रहा है।

कांग्रेस ने की न्याय की मांग

जिला कांग्रेस कमेटी सूरजपुर ने मांग की है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से तत्काल संवाद किया जाए, उनके सम्मान और सुरक्षा को गारंटी दी जाए, शाही स्नान जैसी परंपरा में किसी भी प्रकार की बाधा समाप्त की जाए, दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र संज्ञान नहीं लिया तो यह मुद्दा देशव्यापी आंदोलन का रूप ले सकता है, जिला कांग्रेस कमेटी ने स्पष्ट कहा कि शंकराचार्य का अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सनातन धर्म और भारत की आत्मा का अपमान है।

गणतंत्र दिवस की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर ने सीएसईबी ग्राउंड का किया निरीक्षण

-संवाददाता-
कोरबा, 22 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

कलेक्टर कुणाल दुदावत एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों के संबंध में सीएसईबी ग्राउंड का निरीक्षण किया। उन्होंने मंच व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, गाड़ियों की पार्किंग, झांकी के एंटी-एक्जिट प्लान एवं सुरक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी तैयारियों को समय सीमा में पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। 24 जनवरी को गणतंत्र दिवस के संबंध में अंतिम रिहर्सल किया जाएगा। कलेक्टर ने निगमायुक्त श्री आशुतोष पांडेय को आयोजन स्थल पर मंच निर्माण सहित अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, अपर आयुक्त विनय मिश्रा, एसडीएम कोरबा श्री सरोज महिलागे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। परेड में सीआईएसएफ, पुलिस, नगर सेना एवं एनसीसी, स्काट ग्राइड की टुकड़ियां भाग लेंगे। समारोह सुबह नौ बजे शुरू होगा। समारोह के मुख्य अतिथि द्वारा मुख्यमंत्री के छत्तीसगढ़ वासियों के लिए प्रेषित संदेश का वाचन किया जाएगा। कार्यक्रम में उलूक कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों, डॉक्टरों, पुलिस कर्मियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों सहित विभिन्न विभागों को सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में विभिन्न विभागीय योजनाओं की चर्चित झालकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर सभी शासकीय एवं सार्वजनिक भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी शासकीय एवं सार्वजनिक भवनों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर रोशनी की जाएगी। जनपद कार्यालयों में जनपद अध्यक्ष एवं नगरीय निकायों में नगरीय निकाय के महापौर या अध्यक्षों द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा।

नाबालिग छात्रा की घर वापसी में सिस्टम बना बाधा, एनएसयूआई ने उठाई आवाज

आईडी मिसमैच ने रोकी छात्रा की रिहाई, 6 माह से बैंगलोर में कैद मासूम

पुलिस की गलती से बैंगलोर में कैद मासूम, परिजन 6 माह से न्याय को तरसे

सरकारी चूक की सजा भुगत रही 15 वर्षीय छात्रा, एनएसयूआई ने प्रशासन को घेरा

बिहारपुर की बेटी को कब मिलेगा न्याय ? एनएसयूआई ने प्रशासन से की तत्काल कार्रवाई की मांग



-संवाददाता-
सूरजपुर, 22 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

बिहारपुर निवासी 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा को बैंगलोर से सुरक्षित वापस लाने की मांग को लेकर आज एनएसयूआई ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष आकाश साहू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए छात्रा को शीघ्र स्वदेश वापस लाने की मांग की, ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व विधायक पारस नाथ राजवाड़े, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष भावती राजवाड़े, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अश्विनी सिंह, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज डालमिया, नगर पालिका अध्यक्ष कुसुमलता राजवाड़े एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जफर हैदर विशेष रूप से उपस्थित रहे।

6 माह से बैंगलोर के बाल विकास गृह में है छात्रा

जानकारी देते हुए बताया गया कि ग्राम करौटी, थाना चांदनी, बिहारपुर ब्लॉक ओडगी निवासी राजेन्द्र सिंह की 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री सूरजपुर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में अध्ययनरत थी। पढ़ाई के लिए वह वकील कॉलोनी में किराए के मकान में अपने सहपाठियों के साथ रहकर अध्ययन कर रही थी, दिनांक 30

जुलाई 2025 को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा छात्रा को बहला-फुसला कर ले जाया गया। घटना को छह माह से अधिक समय बीत चुका है, किंतु छात्रा अब तक अपने घर वापस नहीं लौट सकी है, जांच के दौरान पुलिस एवं प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्रा को बैंगलोर के यशवंतपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित बाल विकास गृह में रखा गया है। जिस व्यक्ति के साथ वह गई थी, वह काफी समय पूर्व वापस आ चुका है, परंतु छात्रा अब भी वहीं रह रही है।

प्रशासनिक लापरवाही बनी छात्रा की वापसी में बाधा

परिजनों ने बताया कि जब छात्रा को वापस लाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग सूरजपुर के अधिकारी, कुछ पुलिसकर्मी तथा परिवार का एक सदस्य बैंगलोर गए, तब गंभीर लापरवाही सामने आई, जिन पुलिस कर्मियों के नाम आदेशित सूची में दर्ज थे, वे मौके पर नहीं पहुंचे, बल्कि अन्य पुलिस बल भेज दिए गए। बैंगलोर बाल विकास विभाग द्वारा जब सूची और पुलिसकर्मियों के पहचान पत्र (आईडी) का मिलान किया गया तो वह मेल नहीं खा सका, जिसके चलते अधिकारियों ने छात्रा को सौंपने से इनकार कर दिया, इसी प्रशासनिक चूक के कारण आज भी

नाबालिग छात्रा बैंगलोर में फंसी हुई है और उसके परिजन पिछले कई महीनों से मानसिक, सामाजिक और आर्थिक पीड़ा झेल रहे हैं।

कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग

एनएसयूआई व कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर से मुलाकात कर पूरे मामले में त्वरित हस्तक्षेप करते हुए सही आदेश जारी करने, अधिकृत पुलिस दल भेजने तथा छात्रा को सुरक्षित घर वापस लाने की मांग की, प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यह मामला न केवल एक नाबालिग बच्ची की सुरक्षा से जुड़ा है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर उदाहरण भी है, जिसकी तत्काल जांच और सुधार आवश्यक है।

ज्ञापन सौंपने के दौरान उपस्थित रहे...

इस अवसर पर विष्णु कसेरा, नीरज तायल, मधु साहू, सैयद नदीम, मुस्तफा खान, तनवीर, अफरोज अंसारी, शिवम साहू, लिवनेश सिंह, सुमंत राजवाड़े, हैदर अली, आयुष शांडिल्य, ललित सहित छात्रा के पिता राजेन्द्र सिंह उपस्थित थे, एनएसयूआई ने चेतावनी दी कि यदि छात्रा को शीघ्र वापस नहीं लाया गया तो संगठन आंदोलनात्मक कदम उठाने को मजबूर होगा।

बलौदाबाजार के प्राइवेट स्टील प्लांट में ब्लास्ट, 6 की मौत 5 घायल, गर्म राख से जिंदा जले मजदूर, मृतक बिहार के रहने वाले

बलौदाबाजार, 22 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार जिले के बकुलाही इलाके में स्थित स्पंज आयरन प्लांट में हुए ब्लास्ट से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि डस्ट सेटलिंग चैंबर से गर्म राख (ऐश) ले जा रही पाइपलाइन में लीकेज हो गया था। विस्फोट प्लांट की कोल भट्टी (कोल किलन) में गुरुवार सुबह करीब 9.40 बजे हुआ। ब्लास्ट के दौरान गर्म मलबा (राख) नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिरा, जिससे कई लोग झुलस गए। धमाके के बाद दूर तक धुएं का गुबार दिखा। घायलों को तत्काल भाटापारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (एचएस) और स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से घायलों को बिलासपुर के बर्न ट्रीटमेंट सेंटर भेजा गया है। मृतक बिहार के रहने वाले हैं। कंपनी ने मृतकों के परिजनों को 20 लाख और घायलों को 5 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है।

प्लांट सील, प्रबंधन से पूछताछ

मौके पर कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के साथ जिला प्रशासन



की टीम मौजूद रही। रियल स्टील प्लांट को सील कर दिया गया है। प्लांट प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है। फैक्ट्री निवेश अग्रवाल की बताई जा रही है। कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि बकुलाही क्षेत्र में रियल इस्टाट कंपनी में सुबह करीब 9:40 बजे बड़ा हादसा हुआ। कोल भट्टी (कोल किलन) के डस्ट

सेटलिंग चैंबर से गर्म राख (ऐश) ले जा रही पाइपलाइन में लीकेज हो गया, जिससे गर्म राख नीचे गिर गई। इस हादसे में नीचे काम कर रहे 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए बिलासपुर के बर्न ट्रीटमेंट सेंटर भेजा गया है।



बिहार के रहने वाले हैं मृतक

कलेक्टर ने बताया कि घायल मजदूरों के बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर कलेक्टर से भी संपर्क किया गया है। श्रम विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है, ताकि प्लांट प्रबंधन पर नियम अनुसार कार्रवाई की जा सके। साथ ही

मृतकों के परिवारों और प्रभावित मजदूरों को उचित मुआवजा दिलाया जा सके। आधार कार्ड के माध्यम से मृत मजदूरों की पहचान कर ली गई है। सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। एसपी भावना गुप्ता ने बताया कि इस हादसे में कुल 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इनमें से 6 लोगों की बर्न इंजरी से मौत हो गई।

शुरुआती जांच में पता चला है कि सुबह की शिफ्ट में 50 से ज्यादा मजदूर काम पर मौजूद थे। सभी मजदूरों का एक-एक कर सत्यापन किया जा रहा है।

परिजनों को पूरा मुआवजा दिया जाएगा-प्रबंधन

वहीं प्लांट के मालिक निवेश अग्रवाल ने बताया कि रोज की तरह हादस कीपिंग का काम चल रहा था तभी डीएससी में डस्ट मटेरियल गिरा, जो काफी गर्म रहता है। मटेरियल नीचे काम कर रहे लोगों के ऊपर गिरने से ये हादसा हो गया। प्रबंधन ने कहा कि सरकारी नियमों के साथ कंपनी की ओर से मृतकों और प्रभावितों के परिजनों को पूरा मुआवजा दिया जाएगा। स्पंज आयरन प्लांट में लौह अयस्क से स्पंज आयरन तैयार किया जाता है। यह प्रक्रिया डायरेक्ट रिडक्शन तकनीक से होती है, जिसमें कोयला या गैस की मदद से अयस्क से ऑक्सीडीन हटाई जाती है। इससे बना स्पंज आयरन आगे चलकर स्टील बनाने का कच्चा माल होता है, जिसे स्टील प्लांट में भेजा जाता है।

CGMSC घोटाला... डायसिस इंडिया के मार्केटिंग हेड कुंजल शर्मा गिरफ्तार

27 जनवरी तक पुलिस रिमांड, सरकार को तीन गुना महंगे रिजेंट सप्लाई का आरोप

रायपुर, 22 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी में दर्ज अपराध के तहत डायसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुंबई के मार्केटिंग हेड कुंजल शर्मा को 21 जनवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी कुंजल शर्मा को 22 जनवरी 2026 को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), रायपुर में पेश किया गया, जहां से उसे 27 जनवरी 2026 तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। 18 जनवरी 2026 को CGMSC घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो/आर्थिक अपराध शाखा ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दुर्ग स्थित मोक्षित कॉर्पोरेशन के संचालक शशांक चौपड़ा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में रिकॉर्ड्स एंड मेडिकेयर सिस्टम्स प्रा.लि., पंचकुला के डायरेक्टर अभिषेक कौशल, श्री शारदा इंडस्ट्रीज रायपुर के प्रोप्राइटर राकेश जैन और रिकॉर्ड्स एंड मेडिकेयर सिस्टम्स के लाइजन्स प्रिंस जैन (शशांक चौपड़ा का जीजा) शामिल हैं। इन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर भरा था।

आरोपी 27 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर : गिरफ्तार आरोपियों को 19 जनवरी को स्पेशल कोर्ट (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), रायपुर में पेश किया गया, जहां से उन्हें 27 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। ब्यूरो ने बताया कि जनहित से जुड़ी



'हमर लैब योजना' में शासकीय धन के दुरुपयोग से जुड़े सभी पहलुओं की जांच जारी है। साक्ष्यों के आधार पर आगे भी दावियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कंपनी पॉलिसी नजरअंदाज कर बढ़ाई गई कीमतें : जांच में सामने आया है कि डायसिस कंपनी ने मेडिकल उपकरणों के रिजेंट्स और कंप्यूमेबल्स के लिए निश्चित एमआरपी तय कर रखी थी। इसके बावजूद आरोपी कुंजल शर्मा ने मोक्षित कॉर्पोरेशन को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कंपनी की पॉलिसी को दकियार किया।

शशांक चौपड़ा के साथ रची साजिश : आरोप है कि कुंजल शर्मा ने शशांक चौपड़ा के साथ मिलकर षड्यंत्रपूर्वक तय एमआरपी से कहीं अधिक दरों और रातों को छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को डायसिस कंपनी की ओर से अनधिकृत रूप से भेजा।

नवा रायपुर में 680 करोड़ की लागत से बनेगा 300 बिस्तरों का बॉम्बे हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवाओं के साथ युवाओं को मिलेगा रोजगार, नवा रायपुर बनेगा सेंट्रल इंडिया का हेल्थकेयर हब : सीएम साय

रायपुर, 22 जनवरी 2026। नवा रायपुर को देश के प्रमुख हेल्थकेयर हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में देश के प्रतिष्ठित बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर और नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के मध्य 15 एकड़ भूमि के लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता नवा रायपुर में प्रस्तावित मेडिसिटी के विकास को नई गति देगा। यह परियोजना न केवल राज्य के हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करेगी, बल्कि निवेश के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की तेज और भरोसेमंद प्रशासनिक कार्यप्रणाली का भी उदाहरण बनेगी। राज्य सरकार द्वारा 24 सितंबर 2025 को निवेश आमंत्रण जारी किए जाने के बाद मात्र चार माह के भीतर भूमि चिन्हंकन, आवश्यक स्वीकृतियां और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर ली गई, जो अपने आप में एक नया बेंचमार्क है। नवा रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित 15 एकड़ भूमि पर बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट द्वारा लगभग 680 करोड़ की लागत से 300



बिस्तरों का अत्याधुनिक मल्टी सुपर-स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा। यह अस्पताल ट्रस्ट का देश में चौथा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। इससे पूर्व मुंबई, इंदौर और जयपुर में ट्रस्ट के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। बॉम्बे हॉस्पिटल के माध्यम से कार्डियक साइंस, कैंसर उपचार, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, क्रिटिकल केयर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट सहित कई उन्नत चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके प्रारंभ होने से छत्तीसगढ़

और आसपास के राज्यों के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मुंबई या दिल्ली जैसे महानगरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। इस परियोजना से 500 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है, जिनमें डॉक्टर, सर्जन, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल टेक्नीशियन शामिल होंगे। इसके साथ ही हेल्थकेयर सप्लाई चेन, सेवाओं और सहयोगी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अप्रत्यक्ष रोजगार भी उत्पन्न होंगे, जिससे स्थानीय

अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि बॉम्बे हॉस्पिटल की स्थापना से नवा रायपुर में मेडिसिटी का सपना साकार होने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के नागरिकों को अपने ही राज्य में विश्वस्तरीय सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के निरंतर विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है।

बॉम्बे हॉस्पिटल जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का नवा रायपुर में निवेश करना राज्य की नीतिगत स्थिरता, तेज निर्णय क्षमता और निवेशक-अनुकूल वातावरण पर विश्वास का प्रमाण है। यह परियोजना छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत स्वास्थ्य जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को दिए जा रहे विशेष प्रोत्साहनों और समयबद्ध क्रियावचन का प्रत्यक्ष परिणाम है। इससे नवा रायपुर को सेंट्रल इंडिया के प्रमुख हेल्थकेयर डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

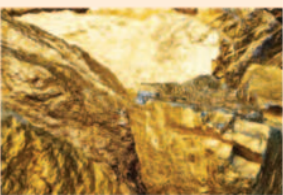
बंदर ने 15 दिन की बच्ची को मां की गोद से छीनकर कुएं में फेंका, डायपर बना जीवनरक्षक

जांजगीर - चां पा, 22 जनवरी 2026। जिले के सिवनी गांव में गुरुवार को एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। घर के आंगन में मां की गोद में बैठी 15 दिन की नवजात बच्ची को एक बंदर अचानक झपट्टा मारकर उठा ले गया और पास स्थित खुले कुएं में फेंक दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मां कुछ समझ पाती, उससे पहले ही बंदर बच्ची को लेकर भाग चुका था। जैसे ही बच्ची कुएं में गिरी, मां की चीख सुनकर ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े और गांव में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत कुएं में उतरकर रेस्क्यू शुरू किया। करीब 10 से 15 मिनट की मशक्कत के बाद बच्ची पानी में दिखाई दी और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि बच्ची ने डायपर पहना हुआ था, जिससे वह पानी में पूरी तरह डूबने से बच गई और उसकी जान बच सकी। कुएं से बाहर निकालते ही मांभूम को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार समय पर रेस्क्यू होने से बच्ची की जान बच गई है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है और किसी गंभीर चोट की पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में बंदरों का आंकड़ बढ़ता जा रहा है और पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों ने प्रशासन से बंदरों पर नियंत्रण और खुले कुओं को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।



तंजानिया गोल्ड माइन में निवेश का झांसा रायपुर के दो व्यवसायियों से करोड़ों की ठगी

रायपुर, 22 जनवरी 2026। राजधानी रायपुर में एक कॉनमेन ने तंजानिया की गोल्ड माइन में निवेश का झांसा देकर दो व्यवसायियों से करोड़ों रुपये की ठगी की है। आरोपी ने खुद को सोने



की खदान का मालिक बताकर निवेशकों को मोटा मुनाफा दिलाने का लालच दिया। पीछित व्यवसायी समर्थ बरडिया और मुकुल चौपड़ा ने बताया कि यश शाह नामक आरोपी ने उन्हें एस.के.एम. बुलियन ट्रेडिंग लिमिटेड नामक फर्म के जरिए भारत और तंजानिया के बैंक खातों में भारी रकम ट्रांसफर कराई। जांच में खुलासा हुआ कि तंजानिया के कानून के अनुसार विदेशी नागरिक सीधे गोल्ड माइन के मालिक या भागीदार नहीं बन सकते। आरोपी ने निवेश पाने के लिए फर्जी दस्तावेज और कटरचित फर्म का सहारा लिया। साथ ही, पीछितों की जानकारी के बिना विदेशी खाते से 70 हजार अमेरिकी डॉलर (लगभग 58 लाख रुपये) भी निकाल लिए गए।

हरियाणा में बैठकर छत्तीसगढ़ में चला रहे थे ऑनलाइन सट्टा, पुलिस ने छापा मार कर 5 को दबोचा, खातों में मिला 8 करोड़ का बैंक ट्रान्जेक्शन

खैरागढ़, 22 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ पुलिस की लगातार कार्रवाई के चलते सट्टा कारोबारियों ने सट्टा ऐप का नाम बदल दिया है और जगह भी बदल दी है। खैरागढ़ जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुये ऐसे ही ऑनलाइन सट्टा खिला रहे पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये सभी हरियाणा में बैठकर छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा-जुआ का संचालन कर रहे थे। इतना ही नहीं पुलिस को चकमा देने के लिए इनके द्वारा शिवा बुक का नाम बदलकर 100 पैन्ल व फेयर प्ले के नाम से ऑनलाइन बैटिंग ऐप चलाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 करोड़ का बैंक ट्रान्जेक्शन का रिकॉर्ड जब्त किया है।

पूर्व में पकड़े गए सदसियों से मिला सुराग : दरअसल, जिले में अवैध गतिविधियों व जुआ सट्टा पर कार्रवाई लगातार जारी है। पूर्व में थाना डूँहखदान क्षेत्र में ऑनलाइन जुआ खेलने वाले



व्यक्ति के विरुद्ध अपराध 187/25 धारा 6,7 छ ग जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 कायम किया गया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को आनलाईन गेमिंग ऐप के माध्यम से जुआ सट्टा का संचालन करते गिरफ्तार किया। पूछताछ में और भी आरोपियों का नाम

सामने आया था। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही थी जिनके बारे में पुछता जानकारी गुराग्राम, हरियाणा में होना पाया गया। पुलिस टीम केसीजी द्वारा लगातार सघन जांच व तलाशी के बाद आरोपियों को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में गेमिंग ऐप संचालित करते दबोचा गया।

CG-SI नियुक्ति रद्द... आबकारी उप निरीक्षक पद पर जारी आदेश निरस्त, तकनीकी कारण बने वजह

रायपुर, 22 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग से जुड़ा एक अहम प्रशासनिक फैसला सामने आया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2024 के तहत आबकारी उप निरीक्षक पद पर जारी की गई नियुक्ति को तकनीकी कारणों के चलते तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इस निर्णय से चयनित अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, वहीं आयोग की चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे हैं। राजधानी रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, CGPSC द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2024 की चयन सूची जारी होने के बाद विभिन्न विभागों में नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे। इसी क्रम में आबकारी विभाग में उप निरीक्षक पद पर भी अभ्यर्थियों को



नियुक्ति दी गई थी। हालांकि अब संबंधित विभाग ने इन नियुक्ति आदेशों को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय तकनीकी कारणों के चलते लिया गया है, हालांकि इन कारणों का विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। सूत्रों की मानें तो चयन प्रक्रिया, पदों की संख्या,

आरक्षण रोस्टर या दस्तावेज सत्यापन से जुड़ी किसी त्रुटि के कारण यह कदम उठाया गया हो सकता है। प्रशासनिक स्तर पर यह भी चर्चा है कि भविष्य में किसी कानूनी जटिलता से बचने के लिए समय रहते नियुक्ति को रद्द किया गया है। इस फैसले से चयनित अभ्यर्थियों में निराशा का माहौल है। जिन उम्मीदवारों को पहले ही नियुक्ति आदेश मिल चुके थे, अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि वर्षों की मेहनत के बाद मिली सफलता के बावजूद नियुक्ति निरस्त होना मानसिक तनाव का कारण बन गया है वहीं, इस पूरे घटनाक्रम ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

राज्यपाल के आदेश पर इस विश्वविद्यालय के कुलसचिव तत्काल प्रभाव से हटाए गए

रायपुर, 22 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एवं कुलाधिपति के आदेश पर महत्वा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन (दुर्ग) के प्रथम कुलसचिव आर.एल. खरे को उनके दायित्व से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया गया है। राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार आर.एल. खरे को कुलसचिव के दायित्व निर्वहन हेतु पूर्व में जारी आदेश को निरस्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के अनुमोदन से की गई है। आदेश 2 जनवरी 2026 से प्रभावशील माना जाएगा। आदेश की प्रति कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव सहित संबंधित अधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। इस आदेश के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन में नए कुलसचिव की नियुक्ति को लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू किए जाने की संभावना है।

